

due to paucity of funds, the proposed line is not likely to merit adequate priority for inclusion in the Fourth Five Year Plan.

Paper Mills in Tripura

4118. Shri Mohammad Ismail
Shri Ganesh Ghosh:
Shri B. K. Modak:
Shri Bhagaban Das:
Shri Jyotirmoy Basu:

Will the Minister of Industrial Development and Company Affairs be pleased to state:

(a) whether Government of Tripura propose to have a Paper Mill, a Plywood Factory and a Jute Mill in Tripura; and

(b) if so, the steps being taken to establish these mills and factories early?

The Minister of Industrial Development and Company Affairs (Shri F. A. Ahmed): (a) Yes, Sir

(b) A licence for the establishment of an undertaking for the manufacture of Plywood has been issued to a private party which they have still to implement.

In February, 1965 a letter of intent was issued to a private party for the setting up of a Jute Mill. This had to be withdrawn, as the party was not in a position to arrange for import of machinery on terms acceptable to Government. At present there is no other proposal for jute manufacturing plant in that State before Government for consideration.

As regards Paper Mill, a Project in the Public Sector will have to be thought of in relation to the overall programme within the Eastern Region within the financial resources that may be available.

पूर्व रेलवे में कारखानों की पदावधि

4119. श्री राजकुमार शस्त्री: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थायवह डिबीजन के सफ़्त कारखानों में कारखाने के पद कमीनर के पद पर उनकी पदावधि की जाने के विषय कसकता उच्च न्यायालय में मकदमा [संख्या 2985 (इम्प्ट्यू), 1966] दायर किया था,

(ख) क्या उच्च न्यायालय ने निवेद्याजा जारी की थी, जिस में सम्पूर्ण पूर्वी रेलवे प्रशासन को अनदेख दिया गया कि वह इस प्रकार की पदावधियाँ मुरतल रोकें;

(ग) क्या उच्च न्यायालय द्वारा निवेद्याजा दी जाने के बाद स्थायवह, घासनसोल, हावड़ा और छनबाद में सँकट कारखानों की कमीनरों के पदों पर पदावधियाँ को रोक दिया गया है;

(घ) क्या यह भी सच है कि दानापुर डिबीजन के अधिकारियों ने डिबीजन सुपरिन्टेंडेंट, दानापुर के आदेश सक्या ई० कार्यालय आदेश सक्या 1822/1966 के द्वारा उक्त निवेद्याजा की अवहेलना करके अनेक मकदमा कारखानों को पदावधत कर दिया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार का इन मामलों क्या कार्यवाही करने का विचार है?

रेलवे मंत्री (श्री वे० सु० गुलाबा):

(क) की नहीं। सेकण्ड कारखाने के पद से कमीनर के पद पर परावर्तन आदेश के विषय नहीं, बल्कि कुछ कालख कारखानों को जीमर-मैन सेट II कलमन की वैकल्पिक सेवी में मनात किये जाने से सम्बन्धित आदेश के विषय कसकता हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था।